THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) 2 new lines, one from Dudhnoi to Depa in Meghalaya and the other from Mig-rendisa to Ditokcherra are likely to be laid in the next S years in the North Eastern region.

Project of Jeevan Rekha Express

402. SHRI PRAMOD MAHAJAN: WiU the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Jeevan Rekha Project has failed for want of proper response; and

(b) if so, what steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sin

(b) Does not arise.

Expenditure incurred on conversion of M.G. into B.G. Lines

403. SHRI S.K.T. RAMACHAN-DRAN: Will the Minister of RAIL WAYS be pleased to state:

(a) the actual expenditure incurred so far during the year 1991-92, towards the implementation of the projects of con-version of metre gauge lines into broad gauge lines, between Madras and Trichirapally and Trichirapally and Din-digal respectively;

(b) the details of the actual works undertaken so far in these two sectors under the projects of conversion;

(c) by when these projects are likely to be completed; and

(d) what steps are being taken to complete the projects within at least three years from the date of commencement of work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Rs. 9.43 crores.

(b) Work is in progress between Madras & Chengalpattu. Work on rest of the section will be taken up shortly.

(c) Within three years, subject to availability of resources.

(d) Adequate funds/P.Way materials as required are being provided to the Railway.

रेल कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

404. चौधरी हरमोहन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और ये सुविधाएं किन-किन क्षेत्रों में प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार रेल कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की है, इसलिए रेलें, रेल कर्मचारियों के आश्रितों के लिए उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का और विस्तार नहीं कर रही हैं।

विवरण

रेल कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. **आवासीय सुविधाएं।**
2. **अस्पतालों, स्वास्थ्य यूनिटों और होमियो-पैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं।**
3. **शैक्षणिक सुविधाएं—रेलवे विद्यालय तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावास की**

व्यवस्था, छात्रावास के लिए आर्थिक सहायता, शैक्षणिक भत्ता, छात्रवृत्तियां, अनुदान सहायता देना आदि।

4. खेलकूद, स्काउट और सांस्कृतिक कार्य-कलापों को बढ़ावा देना।

5. सहकारी समितियां।

6. कार्य स्थलों पर कर्मचारी कैंटीन।

7. अवकाश गृह।

8. कर्मचारी हित निधि के माध्यम से संकट के समय राहत।

9. मनोरंजन सुविधाएं—संस्थानों और कलबों की व्यवस्था।

10. यात्रा सुविधाएं।

रेलवे भूमि का अतिक्रमण

405. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त भूमि का अतिक्रमण हटाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) अतिक्रमण को रोकने का कार्य किन-किन अधिकारियों को सौंपा गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में 282.45 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है। ब्यौरा इस प्रकार है:—

मध्य रेलवे	:	2.40 हेक्टेयर
पूर्व रेलवे	:	0.13 "
उत्तर रेलवे	:	186.50 "
पूर्वोत्तर रेलवे	:	93.24 "
पश्चिम रेलवे	:	0.18 "

(ग) और (घ) अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इंजीनियरी विभाग, वाणिज्यिक विभाग और रे०सु०ब० के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में अतिक्रमणों को रोकने का काम सौंपा गया है। स्थानान्तरणों के कारण ये अधिकारी बदलते रहते हैं। जब कभी ऐसा अवसर आता है ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए मौजूदा नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

उत्तर रेलवे जोन में रोजगार में कमी होना

406. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने रोजगार सृजित किये जाने का विचार है;

(ग) उत्तर रेलवे में पिछले तीन वर्षों से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें से कितने कर्मचारी नैमित्तिक हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मकारों की भर्ती की गई थी और उनमें से कितने मजदूर नैमित्तिक थे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Ratio of Railway Track in Orissa

407. SHRIMATI ILA PANDA:
SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the Km. ratio of Railway track per 100 Sq. Km. in Orissa;

(b) what is the National average ratio track and by what ratio the railway Kilometerage of Orissa deviate from the National average;

(c) how much more Km. of Railway track is proposed to be laid in Orissa during the 8th Five Year Plan period; and

(d) what amount has been sanctioned for this purpose?